* 19th Year
* Issue: 249
* 16.01.2026 (FRIDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

लोकतंत्र को लेकर भारत ने दुनिया को गलत साबित किया-पीएम मोदी

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है, और वैश्विक एजेंडा के केंद्र में इस क्षेत्र की चिंताओं को लगातार प्राथमिकता देने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। संसद भवन में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें समेलन (सीएसपीओसी), 2026 में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके नवाचारों से पूरे वैश्विक दक्षिण और राष्ट्रमंडल देशों को लाभ मिले, और साथ ही सहयोगी देशों के लिए ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि वे भारत में लागू की जा रही प्रणालियों के समान प्रणालियाँ विकसित कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है।

जी20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक एजेंडा के केंद्र में वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को रखा है। भारत का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हम जो भी नवाचार करें, उससे पूरे वैश्विक दक्षिण और राष्ट्रमंडल देशों को लाभ मिले। हम ओपन-सोर्स तकनीकी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि वैश्विक दक्षिण में हमारे सहयोगी देश भी भारत जैसी प्रणालियाँ विकसित कर सकें। प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि इसकी पहचान अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता से होती है।

जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, हम समावेशी रूप से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे। इसी प्रतिबद्धता के कारण भारत ने हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत में लोकतंत्र वास्तव में परिणाम देता है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना। उन्होंने आगे कहा, हम बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और जन कल्याण की इसी भावना के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

स्वाति मालीवाल ने अकाल तख्त पर भगवंत मान पर साधा निशाना

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को पंजाब के मुज़्यमंत्री भगवंत मान पर श्री अकाल तज़्त के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर जमकर हमला बोला। मान पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि वे धार्मिक और सरकारी स्थलों पर जाने से पहले शराब पीते हैं और अपनी सरकार में चोरों और बदमाशों को जगह देते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मान ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपये छिपा रहे हैं। एज़्स पर पोस्ट में सांसद मालीवाल ने लिखा कि करोड़ों रुपये ऑस्ट्रेलिया में ठिकाने लगाके, शराब पीकर गुरुद्वारा-मंदिर-सरकारी मीटिंग-संसद में जाने वाले। चोरों-गुंडों को अपनी सरकार में जगह देने वाले एक शख्स, पवित्र श्री अकाल तखूत पर घटिया बयान और आरोप लगा रहे है।

जांच एजेंसी के काम में दखल गंभीर मामला, बंगाल सरकार और पुलिस को नोटिस

कोलकाता १५/०१ (संवाददाता):: ममता बनर्जी को झटका लगा है ज़्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की काम में पुलिस की दखल का मामला गंभीर है। कोर्ट ने दो हज़्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही, ईडी के छापे से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ईडी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियबत्रा रॉय सहित प्रमुख पुलिस अधिकारियों को एजेंसी की छापेमारी में कथित हस्तक्षेप के लिए निलंबित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने कहा, यह एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। पहले भी, जब भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है, मुज़्यमंत्री जबरदस्ती उनके परिसर में घुस जाती हैं। एसजी मेहता ने कहा कि डायरेज़्टर और कमिश्नर उनके साथ थे। वे सहयोगी थे। अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं के साथ धरना दिया। एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है... सीबीआई के संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया...पत्थर फेंके गए।

ईरान में फंसे करीब हजारों भारतीय छात्र, ओवैसी-उमर ने जयशंकर से लगाई वापसी की गुहार

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और जज़्मू-कश्मीर के मुज़्यमंत्री उमर अज़्दुल्ला ने केंद्र सरकार से ईरान में जारी अशांति के बीच फंसे भारतीय छात्रों की तत्काल मदद करने का आग्रह किया है। ओवैसी ने कहा कि इन छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का ईरान के विदेश मंत्री से बात करना एक अच्छा कदम है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि केवल बातचीत पर्याप्त नहीं है और छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कई चिंतित अभिभावकों ने उनसे संपर्क किया है। ओवैसी के अनुसार, ईरान के शाहिद बेहेश्टी विश्वविद्यालय में लगभग 70 से 80 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जिनमें हैदराबाद के पांच से आठ छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान भर में सैकड़ों भारतीय छात्र हैं जो अब भयभीत और असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि ईरान में इंटरनेट ठप है। दूसरी बात, अभिभावक टिकट खरीदकर अपने बच्चों को भेज भी नहीं सकते। तीसरी बात, कई छात्र गरीब परिवारों से हैं और उनके पास टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि विश्वविद्यालय छात्रों के पासपोर्ट वापस नहीं कर रहा है, जिसके कारण वे ईरान छोड़कर भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। ओवैसी ने कहा कि माता-पिता बेहद परेशान और चिंतित हैं ज़्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ ज़्या हो रहा है। उन्होंने भारत सरकार से सभी फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए शीघ्र ही एक स्पष्ट निकासी योजना तैयार करने का आग्रह किया। जज़्मू-कश्मीर के पूर्व मुज़्यमंत्री उमर अज़्दुल्ला ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से ईरान में तेजी से बदलती स्थिति के बारे में बात की है, जहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

जवानों के साहस को सलाम, देश उनकी निस्वार्थ सेवा का सदा ऋणी रहेगा-जयशंकर

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता):विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को सलाम किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा आज सेना दिवस पर हमारे सैनिकों के साहस और दृढ़ संकल्प को सलाम। राष्ट्र उनके निस्वार्थ सेवा के लिए उनके और उनके परिवारों के प्रति सदा कृतज्ञ रहेगा। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, यह दिवस लेज़्टिनेंट जनरल कोडंडेरा एम. कारियाप्पा (जो बाद में फील्ड मार्शल बने) द्वारा 15 जनवरी 1949 को भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस दिन को उन सैनिकों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि बताया, जो दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पत्र में लिखा कि मैं 2026 के सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को हार्दिक बधाई देती हूँ। सेना दिवस हमारे उन सैनिकों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है जो राष्ट्र की सेवा में अडिग हैं। भारतीय सेना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। इसने सीमाओं की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन बचाने में व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता और वीरता की उच्चतम परंपराओं को निरंतर कायम रखा है। मैं ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और उत्कृष्ट सफलता की सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखेगी और आर्थिक प्रगति एवं समावेशी विकास को सुगम बनाएगी।

पश्चिम बंगाल में पुलिस बनी ममता का औजार-रविशंकर प्रसाद

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप को लेकर आलोचना की है।

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने मुज़्यमंत्री के आई-पीएसी कार्यालय जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न तो टीएमसी का कार्यालय है और न ही किसी पार्टी नेता का निवास स्थान। प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कल पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के प्रयासों के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुज़्यमंत्री के हाथों का औजार बन गई है, और कहा कि राज्य में कानून प्रवर्तन प्रणाली का दुरुपयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

मुंबई में थमा मतदान, भाजपा-महायुति और ठाकरे बंधुओं के बीच सज़ा का महासंग्राम

मुंबई १५/०१ (संवाददाता): मुंबई में महत्वपूर्ण बीएमसी चुनावों के साथ-साथ महाराष्ट्र भर के 28 अन्य नगर निगमों के चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मुंबई में हुए महत्वपूर्ण बीएमसी चुनावों में यह आरोप लगने से विवाद खड़ा हो गया कि मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही को एसीटोन से आसानी से मिटाया जा सकता है। यह दावा इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ और कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। इस बीच, चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर इस आशंका को खारिज कर दिया कि कोई मतदाता दो बार वोट डाल सकता है और घटना की जांच के आदेश भी दिए।

देश के सबसे अमीर महानगरपालिका के 227 पार्षदों को चुनने के लिए सुबह 7.30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ जो शाम 5ः30 बजे समाप्त हुआ। बीएमसी पार्षद चुने जाने के लिए करीब 1,700 उज़्मीदवार मैदान में हैं। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक अपराह्न 1.30 बजे तक पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 114 में सबसे अधिक 41.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो मुंबई के कुछ हिस्सों में मजबूत मतदाता भागीदारी को दर्शाता है। दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 227 में शुरुआती छह घंटों में सबसे कम 11.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह मतदान शुरू हुआ और सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। निकाय चुनाव में मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उज़्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक शामिल हैं। अक्षय कुमार, आमिर खान, गुलजार, सलीम खान, परेश रावल, हेमा मालिनी, जॉन अब्राहम, सोनाली बेंद्रे, ईशा कोप्पिकर, तमन्ना भाटिया, दिव्या दज़ा और गायक कैलाश खेर जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजली, बेटी सारा और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी अपने-अपने वार्ड में मतदान किया। मुंबई में दोपहर 3ः30 बजे तक 41.08त्न मतदान दर्ज किया गया। चल रहे बीएमसी चुनावों में सलमान खान, जाह्नवी कपूर, सौज़्या टंडन और अन्य सहित कई बॉलीवुड हस्तियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखा गया। कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शुरुआती मतदान करने वालों में शामिल थीं। महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नाइक और उनके परिवार ने बोनकोड मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, जबकि पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र ने उच्च आय वाले मतदाताओं की शिकायत करने के बावजूद वोट न डालने की आलोचना की। शिवसेना (यूबीटी) के नेता आनंद दुबे और अनिल परब ने भी मुंबई में मतदान किया और मतदान केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं को लेकर चिंता जताई। दुबे ने चुनाव आयोग की वेबसाइट में खामियों और डिजिटल मतपत्रों के प्रदर्शन में अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जबकि परब ने दावा किया कि चुनाव स्याही को मिटाया जा सकता है, जिससे संभावित छेड़छाड़ का संकेत मिलता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुज़्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मतदाता नामों के गायब होने, पुरानी ईवीएम मशीनों और स्याही की अनियमितताओं का हवाला देते हुए प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। ठाकरे ने इन घटनाओं को ॐलोकतंत्र पर खुला हमलाॐ करार दिया और इन्हें ॐएक राष्ट्र एक चुनावॐ प्रस्ताव से जुड़ी व्यापक चिंताओं से जोड़ा।

विविध समाचार

ईडी छापेमारी में बाधा डालना ममता बनर्जी को पड़ा महँगा, सुप्रीम कोर्ट ने ने भेजा नोटिस

कोलकाता १५/०१ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में सज़ारुढ़ तृणमूल कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा ज़्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस आरोप को ''बेहद गंभीर'' बताया है कि पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसकी जांच में ''बाधा पैदा की''। साथ ही न्यायालय ने इस बात की समीक्षा करने पर सहमति जताई कि ज़्या किसी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी गंभीर अपराध के मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर सकती हैं।

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है जिन्होंने आठ जनवरी को 'इंडियन पॉलिटिकल एज़्शन कमेटी' (आई-पैक) कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। अदालत ने राज्य पुलिस को छापेमारी की कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मुज़्यमंत्री बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें आई-पैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच का अनुरोध किया गया है।

पीठ ने कहा, ''हमें लगता है कि देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए इस मुद्दे की समीक्षा करना आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की छत्रछाया में संरक्षण न मिल सके।'' पीठ ने कहा, ''इसमें बड़े सवाल शामिल हैं और उठाए गए हैं, जिन्हें अगर अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो स्थिति और बिगड़ जाएगी तथा अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग संगठनों के शासन को देखते हुए किसी न किसी राज्य में अराजकता की स्थिति बनी रहेगी।''

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के चुनावी काम में हस्तक्षेप करने की शक्ति किसी केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं है लेकिन साथ ही यदि केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए सद्भावना से काम कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि ज़्या दलगत गतिविधि की आड़ में एजेंसियों को अपने कर्तव्य निभाने से रोका जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ईडी की छापेमारी संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कलकज़ा उच्च न्यायालय में हुए हंगामे से वह अत्यंत व्यथित है। हम आपको याद दिला दें कि कलकज़ा उच्च न्यायालय ने राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी आई-पैक से जुड़े स्थानों पर ईडी की छापेमारी और जज़्ती कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अदालत कक्ष के भीतर ''अनियंत्रित अराजकता'' का हवाला देते हुए 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि जांच एजेंसी की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ''दखलअंदाजी और बाधा'' एक बेहद चौंकाने वाले चलन को दर्शाती हैं।

ईडी का आरोप है कि छापे के दौरान मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया, पुलिस के सहयोग से डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज हटवाए और बिना किसी जज़्ती के जांच अधिकारियों को कार्रवाई समाप्त करने के लिए मजबूर किया। न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक चिंताजनक चलन को दर्शाता है, जब भी वैधानिक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो हस्तक्षेप किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुज़्यमंत्री स्वयं छापेमारी स्थल पर पहुंचीं और

जांच से जुड़े अहम सबूत अपने साथ ले गईं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी, इसके बावजूद पुलिस महानिदेशक, मुज़्यमंत्री, पुलिस आयुक्त, क्षेत्र के उपायुक्त और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बिना अधिकार के सामग्री हटाई गई। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पहले भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का जब-जब प्रयोग किया, ममता बनर्जी वहां पहुंचीं और उन्होंने दखलअंदाजी की।

तुषार मेहता ने कहा, ''यह एक बेहद चौंकाने वाले चलन को दर्शाता है।'' उन्होंने कहा कि इससे इस प्रकार के कृत्यों को और बढ़ावा मिलेगा तथा केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ''राज्यों को लगेगा कि वे दखल दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और फिर धरने पर बैठ सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए; जो अधिकारी वहां स्पष्ट रूप से मौजूद थे, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए।'' तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे साक्ष्य हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आई-पैक कार्यालय में आपज़िजनक सामग्री मौजूद थी। उन्होंने कहा, ''सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दें और जो हो रहा है, कृपया उसका संज्ञान लें। हम यहां अपने अधिकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए जज़्ती नहीं करते।'' तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी संज़्या में वकील और अन्य लोग कलकज़ा उच्च न्यायालय में दाखिल हो गए थे जिसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा, ''ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ले लेता है।''

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिज़्बल ने तुषार मेहता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहले इस मामले की सुनवाई कलकज़ा उच्च न्यायालय में होनी चाहिए तथा उचित न्यायिक पदानुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ईडी समानांतर कार्यवाही कर रही है। कपिल सिज़्बल ने छापे की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी हवाला देते हुए कहा, ''यह सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल उपकरण ले लिए गए थे। मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सभी उपकरण ले जाए जाने का आरोप झूठ है, जिसकी पुष्टि ईडी के अपने पंचनामे से होती है।'' उन्होंने कहा, ''कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था; तब से ईडी ज़्या कर रही थी? चुनावों के दौरान इतनी जल्दबाजी ज़्यों?'' मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिज़्बल ने दलील दी कि इस मामले में पहले उच्च न्यायालय को सुनवाई कर निर्णय देना चाहिए था, ज़्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत वही उपयुक्त मंच है। उन्होंने कहा कि समानांतर कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है। कपिल सिज़्बल ने यह भी कहा कि आई पैक के पास राजनीतिक दल से जुड़ा संवेदनशील डाटा है और प्रवर्तन निदेशालय को यह जानकारी थी।

वहीं राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने याचिका के सुनवाई योग्य होने पर कड़ी आपज़ि जताई। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का सीधे सर्वोच्च न्यायालय आना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है। साथ ही उन्होंने ईडी के सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया ज़्योंकि समान राहतें पहले ही हाई कोर्ट में मांगी जा चुकी हैं। सिंघवी ने कहा कि या तो याचिका में लगाए गए आरोप गलत हैं या फिर पंचनामा गलत है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी दलील दी कि राज्य को छापे की सूचना केवल सुबह साढ़े ग्यारह बजे एक साधारण ईमेल के माध्यम से दी गई, जबकि तलाशी सुबह पौने सात बजे शुरू हो चुकी थी।

वहीं भाजपा ने कहा है कि अदालत का आदेश तृणमूल कांग्रेस के लिए करारा झटका है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, %%सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी स्न्नद्वक्र (ममता बनर्जी की सरकार ने श्वष्ठ अफसरों के खिलाफ) पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में यह कैसा जंगलराज चल रहा है? मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका उज़र देना चाहिए।%% उन्होंने कहा कि ञ्जरूष्ट ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले ञ्जरूष्ट के लीगल सेल ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा और कहा कि सभी लोग हाई कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, ममता बनर्जी जंगलराज का प्रतीक हैं।卐

हम आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में ईडी की यह याचिका आठ जनवरी की उन घटनाओं के बाद दायर की गई है जब कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में साल्टलेक स्थित आई-पैक के कार्यालय और कोलकाता में उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी के छापों के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों को बाधाओं का सामना करना पड़ा था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी परिसर में दाखिल हुईं और जांच से संबंधित ''महत्वपूर्ण'' साक्ष्य अपने साथ ले गईं। वहीं मुज़्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया है और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की जांच में ''बाधा डालने'' के आरोप से इंकार किया है। राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है।

बहरहाल, इस मामले ने केंद्र और राज्य के बीच टकराव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस संवेदनशील मामले के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार से विचार होगा।

काशी तमिल संगमम पर मोदी का बड़ा बयान, बोले-एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हुई मजबूत

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पोंगल के अवसर पर काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी पहलों के विकास पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि इन पहलों ने %एक भारत श्रेष्ठ भारत% की भावना को और मजबूत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ की अपनी हालिया यात्रा में इन पहलों को जनता ने खूब सराहा। अपने आधिकारिक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ की अपनी हालिया यात्रा में, मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे प्रयासों की सराहना की। आज, पोंगल के विशेष अवसर पर, मैंने काशी तमिल संगमम के विकास और इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करने के बारे में अपने विचार साझा किए।

अपने आधिकारिक ज़्लॉग के माध्यम से उन्होंने कहा, काशी का तमिल लोगों और संस्कृति से गहरा संबंध है। बाबा विश्वनाथ काशी में निवास करते हैं, जबकि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है।

तमिलनाडु के तेनकासी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। संत कुमारगुरुपरार स्वामीगल ने अपनी आध्यात्मिकता, विद्वज़ा और संस्था निर्माण के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक अटूट संबंध स्थापित किया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के महानतम

सपूतों में से एक महाकवि सुब्रमण्यम भारती को काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागृति का स्थान मिला। यहीं पर उनका राष्ट्रवाद गहरा हुआ, उनकी कविताएं निखरीं और एक स्वतंत्र, एकजुट भारत का उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस घनिष्ठ संबंध को उजागर करते हैं।

काशी-तमिल संगमम का पहला संस्करण 2022 में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने ज़्लॉग में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के विद्वान, कारीगर, छात्र, किसान, लेखक, पेशेवर और कई अन्य लोग काशी, प्रयागराज और अयोध्या गए थे।

उन्होंने बताया कि बाद के संस्करणों ने इस प्रयास के दायरे और गहराई को बढ़ाया। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य निरंतर नए विषयों, नवीन प्रारूपों और गहन सहभागिता को शामिल करना था, ताकि संगमम अपने मूल सिद्धांतों से जुड़ा रहते हुए लगातार विकसित होता रहे। 2023 के दूसरे संस्करण में, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया ताकि भाषा लोगों के लिए बाधा न बने। तीसरे संस्करण में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही, अकादमिक चर्चाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों और अंत:क्रियाओं में अधिक भागीदारी देखी गई। इन आयोजनों में हजारों लोगों ने भाग लिया है।

मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उठाए सवाल

वाराणसी१५/०१ (संवाददाता):कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को वाराणसी के प्रसिद्ध श्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट के प्रस्तावित रूपांतरण पर सवाल उठाते हुए इसे बेस्वाद सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण का प्रयास बताया, जो सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर कई मंदिरों, छोटे-बड़े तीर्थस्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है।मल्लिकार्जुन खर्गे ने पूछा कि लाखों लोग हर साल अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष की तलाश में काशी आते हैं।

ज़्या आपका इरादा इन श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात करने का है?खरगे ने कथित तौर पर ध्वस्त की गई मूर्तियों और बुलडोजरों की तस्वीरें और वीडियो ङ्ग पर साझा किए। खरगे ने ङ्ग पर लिखा कि बेस्वाद सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट कर दिया है। आप चाहते हैं कि ऐतिहासिक विरासत का हर टुकड़ा मिटा दिया जाए और उस पर सिर्फ आपकी नामपट्टिका चिपका दी जाए।खरगे ने कहा कि गुप्त काल में स्थापित और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित इस दुर्लभ धरोहर को ध्वस्त करना एक अपराध है। उन्होंने पूछा कि ज़्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने का इरादा है? कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि आपने पानी, जंगल, पहाड़ - सब कुछ उन्हें सौंप दिया; अब सांस्कृतिक धरोहर की बारी है। देश की जनता के आपसे दो सवाल हैं - ज़्या धरोहर को संरक्षित करते हुए जीर्णोद्धार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता था? 2. मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर की चपेट में आने वाली सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी ज़्यों चलाई गई और उन्हें मलबे में ज़्यों फेंक दिया गया? ज़्या उन्हें किसी संग्रहालय में संरक्षित नहीं किया जा सकता था?मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जुलाई, 2023 को आधारशिला रखने के साथ हुई थी। इस परियोजना की कुल जीर्णोद्धार लागत लगभग 17.56 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। नए मणिकर्णिका घाट की छत पर विशेष अतिथियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, रैंप, दर्शन क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलज़्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जुबिन गर्ग की मौत पर सिंगापुर पुलिस सही या असम एसआईटी की बात सही?

नयी दिल्ली १५/०१ (संवाददाता): सिंगापुर में असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर सामने आई जानकारियों ने एक ओर जहां घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर भारत के भीतर जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। हम आपको बता दें कि सिंगापुर की एक अदालत में बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार जुबीन गर्ग की मृत्यु लाजरस आइलैंड के पास डूबने से हुई और इसमें किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक कृत्य के संकेत नहीं मिले हैं।

सिंगापुर पुलिस ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर को जुबीन गर्ग लगभग बीस मित्रों और सहकर्मियों के साथ एक याट पर सवार थे। यह याट मारिना एट केपल बे से रवाना होकर लाजरस और सेंट जॉन्स आइलैंड के बीच रुकी थी। इस दौरान याट पर नाश्ता, पेय और शराब का सेवन हुआ। कई गवाहों के अनुसार जुबीन गर्ग ने जिन और व्हिस्की सहित कई कप शराब पी थी। जांच में यह भी सामने आया कि उस समय वह अत्यधिक नशे में थे।

पुलिस के अनुसार जुबीन गर्ग ने पहले एक बड़ी लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की, लेकिन थकान की शिकायत करते हुए याट पर लौट आए। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा तैरने का फैसला किया तो उन्हें एक छोटी लाइफ जैकेट दी गई, जिसे उन्होंने पहनने से इंकार कर दिया। वह बिना लाइफ जैकेट के अकेले लाजरस आइलैंड की दिशा में तैरने लगे। गवाहों ने बताया कि उन्हें वापस आने के लिए आवाज दी गई, जिस पर वह मुड़े भी, लेकिन कुछ ही देर में उनका शरीर ढीला पड़ गया और वह पानी में औंधे तैरते दिखे।

याट पर मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव की कोशिश की और सीपीआर दिया गया। नौ मिनट के भीतर पुलिस कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी। उन्हें सिंगापुर जनरल

हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शाम पांच बजकर पंद्रह मिनट पर मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया। शरीर पर पाए गए कुछ चोट के निशान सीपीआर और बचाव प्रयासों के दौरान के माने गए। टॉज़्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार जुबीन गर्ग के रक्त में शराब की मात्रा 333 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर थी, जो सिंगापुर की कानूनी सीमा से चार गुना से अधिक है। रिपोर्ट में उनके उच्च रक्तचाप और मिर्गी की दवाओं के अंश भी पाए गए, लेकिन किसी अन्य नशीले पदार्थ के संकेत नहीं मिले। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि घटना वाले दिन उन्होंने मिर्गी की दवा समय पर ली थी या नहीं। सिंगापुर पुलिस ने साफ कहा है कि उन्हें किसी तरह की साजिश या जबरन पानी में धकेले जाने के सबूत नहीं मिले हैं। अदालत में यह भी कहा गया कि जुबीन गर्ग में आत्मघाती प्रवृज़ि नहीं थी और उन्होंने स्वयं तैरने के लिए पानी में छलांग लगाई थी। इस मामले में कोरोनर कोर्ट द्वारा एक तटस्थ निष्कर्ष जैसे दुर्घटनावश मृत्यु दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई है।

इसके विपरीत भारत में, खासकर असम में, इस मृत्यु को लेकर तस्वीर अलग दिखाई देती है। असम पुलिस की विशेष जांच टीम और सीआईडी ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें आयोजनकर्ता श्यामकानु महंता, जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके रिश्तेदार संदीपन गर्ग और दो निजी सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। गुवाहाटी की अदालत ने पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है।

असम के मुज़्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इसे न्याय की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा है कि सिंगापुर पुलिस और असम पुलिस की टीमों के बीच समन्वय बैठक होगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि जब सिंगापुर प्रशासन मृत्यु को प्राकृतिक और दुर्घटनाजन्य बता रहा है, तो असम सरकार किस आधार पर इसे हत्या बता रही है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि किस निष्कर्ष पर भरोसा किया जाए।

देखा जाये तो जुबिन गर्ग की मृत्यु केवल एक लोकप्रिय कलाकार के असमय चले जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब भावनाएं, राजनीति और जांच एक साथ उलझ जाती हैं, तो सच तक पहुंचना कितना जटिल हो जाता है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

किसी भी छात्र के लिए उसके करियर ऑप्शन का चयन करना एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय है। एक बार जब छात्र अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते है तो वे अपने करियर को एक शेप देना चाहते है। आर्टस में बैचलर डिग्री यानी बीए एक ऐसा कोर्स है, जिसे अधिकतर बच्चे चुनते है।

बी.ए. करने के बाद इन करियर फील्ड में करें ट्राई

आर्टर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बीए करना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। हालांकि, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें आप इंगलिश से लेकर पॉलिटिक्स और मनोविज्ञान तक किसी खास विषय को चुनते है।

अमूमन यह माना जाता है कि बीए करने के बाद करियर ऑप्शन सीमित हो जाते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप बीए करने के बाद कई अलग-अलग फील्ड में अपना करियर देख सकते है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि बीए करने के बाद आप किन फील्ड में करियर बना सकते है-

जर्नलिज्म में आजमाएं हाथ

बीए करने के बाद एडवरटाइजिंग या जर्नलिज्म की फील्ड में करियर के अवसर देखे जा सकते है। आप बीए करने के बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़ा कोर्स कर सकते है। इसके बाद आप टीवी से लेकर रेडियो, अखबार व ऑनलाइन वेबसाइट्स आदि के लिए काम कर सकते है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म, पॉडकास्ट, ब्लॉग और एड आदि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए है।

सिविल सर्विसेज की करें तैयारी

अगर आप चाहें तो बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे यूपीएससी आदि की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टेट लेवल एग्जाम का हिस्सा बनें।

अगर आप इसे क्लीयर कर पाते हैं तो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बन जाते हैं।

करें प्रोफेशनल राइटिंग

बीए करने के बाद आप प्रोफेशनल राइटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमा सकते हैं। आमतौर पर, यह एक क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें आप अपने विचारों को बेहद ही खास तरह से पेश करते हैं। यदि आपके पास साहित्य में डिग्री है, तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट, से लेकर भाषण, स्क्रीनप्ले, कविताएं आदि लिख सकते हैं। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप प्रोफेशनल राइटिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते है।

करें लॉ

अगर आप बीए की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते है, तो आप बैचलर ऑफ लॉ या एलएलबी चुन सकते है। इस तीन साल के कोर्स के बाद आपको लीगल रीजनिंग से लेकर एनवायरनमेंटल लॉ, इंश्योरेंस लॉ आदि की गहन जानकारी हो जाती है। आप चाहें तो इसके बाद एलएलएम भी कर सकते है।

करें बिजनेस मैनेजमेंट

बीए करने के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। यह एक साल का शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें छात्रों को अलग-अलग बिजनेस एक्टिविटीज और मैनेजमेंट से जुड़े सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। इसके बाद आप कई अलग-अलग आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकते है या फिर खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं।

बॉस से छुट्टी मांगते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

बॉस से छुट्टी मांगना आमतौर पर आसान नहीं होता है। कई बार प्लान बनाने से पहले ही सोचना होता है कि छुट्टी कैसे मिलेगी। हालांकि, कई बार छुट्टी लेने के कुछ और तरीकों को भी अपनाकर आप अपने बॉस से लंबी छुट्टी ले सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाते है तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

प्री प्लान करें

छुट्टी के लिए अचानक से बोलने पर हो सकता है कि आपको छुट्टी नहीं मिले। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको अपने बॉस से पहले से बात कर लेना चाहिए। ऐसे में आपको आसानी से छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा, आपकी गैर-मौजूदगी में आपका काम कौन संभालने वाला है, इसके बारे में भी आपको अपने बॉस से बात कर लेना चाहिए।

बैकअप प्लान करें

लंबी छुट्टी अप्लाई करते समय आपको बैकअप का प्लान तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आपकी गैर-मौजूदगी में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो। बैकअप बनाने के बाद अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते है, तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी।

छुट्टी का कारण

अगर आपको अचानक छुट्टी चाहिए, तो सॉलिड कारण लेकर ही बॉस के पास छुट्टी मांगने जाना चाहिए। अगर आप यह बोलेंगे कि आपको घूमने जाना है, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी न मिल पाए। ऐसे में आपको पहले से कारण तैयार रखना होगा कि आपको अपने बॉस से क्या कहना है।

बॉस का मूड देखकर बात करें

आपको छुट्टी मांगने से पहले अपने बॉस का मूड देख लेना चाहिए। अगर आपके बॉस का मूड अच्छा है, तो आपको तुरंत छुट्टी मिल सकती है। बॉस का मूड खराब होने पर आपको छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मूड के हिसाब से ही आपको बात करना चाहिए।

अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है साइंस की फील्ड

साइंस के क्षेत्र में अच्छे कोर्स करने के बाद, छात्र मालामाल हो सकते हैं, जो उन्हें अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते है। यहां कुछ कोर्स हैं जो छात्रों को साइंस क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इन कोर्स के साथ-साथ, छात्रों को निरंतर अध्ययन करने का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिल सकता है।

स्पेस टेक्नोलॉजी

स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत कॉस्मोलॉजी, स्टारर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैटीरियोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, रडार टेक्नीशियन, सैटेलाइट टेक्नीशियन आदि के रूप में नासा, इसरो एवं डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स के साथ बारहवीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम पास करने के बाद आप स्पेस साइंस के बैचलर प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। स्नातक के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप अगर इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
- तिरुवनंतपुरम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर।
- आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जरवेशनल साइंसेज,
- नैनीताल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु।

फूड टेक्नोलॉजी

अच्छे खानपान का शौक रखने के साथ फूड प्रोडक्ट में प्रयोग होने वाले रसायनों, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, उन्हें पैक करने के तरीकों एवं मार्केटिंग से संबंधित बातों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन कर उभरा है। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में छात्र फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, फूड रिसर्च लेबोरेटरी, होटल, रेस्टोरेंटों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करियर की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या होम साइंस के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आप फूड साइंस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। बैचलर डिग्री करने के बाद फूड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अन्य क्षेत्रों में एडवांस डिग्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। स्नातक के बाद परास्नातक व रिसर्च करने का विकल्प भी है।

कहां से करें कोर्स

- सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी
- नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
- राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन
- नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अन्ना यूनिवर्सिटी

मरीन इंजीनियरिंग

मरीन इंजीनियरिंग असल में इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें जहाजों, नावों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को डिजाइन किया जाता है। मरीन इंजीनियर समुद्री जहाज के सफलतापूर्वक संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और समुद्र एवं उसके आसपास उपयोग की जाने वाली मशीनों का डिजाइन, रखरखाव, निर्माण करते है। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं प्राइवेट शिपिंग कंपनियों, से क्राफ्ट डिजाइनिंग एवं बिल्डिंग, इंजन प्रोडक्शन फर्म में आकर्षक जॉब हासिल कर सकते हैं। मरीन इंजीनियर के लिए भारत और विदेश में भी करियर के अवसरों की एक विस्तृत गुंजाइश है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विभाग में जॉब कर सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

- साइंस बैकग्राउंड के छात्र मरीन इंजीनियरिंग या ओशेन इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक कोर्स के साथ इस करियर में दाखिल हो सकते है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इस विषय में मास्टर्स कर सकते है।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, कोलकाता
- आईआईटी मद्रास
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते है।

फॉरेंसिक साइंस

फॉरेंसिक साइंस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी घटना से जुड़े छोटे-छोटे सुराग के जरिये मुजरिम तक पहुंचने और उनसे संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के काम करते हैं। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के छात्र है और जुर्म करने वाले को किसी भी हाल में सामने लाने का जुनून रखते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब के मौके उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), स्टेट पुलिस फोर्स के क्राइम सेल, गवर्नमेंट व स्टेट फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते है। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते है। आप चाहें तो फॉरेंसिक टीचर के रूप में भी करियर बना सकते है।

योग्यता क्या होगी?

साइंस स्ट्रीम से बारहवीं पास करने के बाद आप फॉरेंसिक साइंस में स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के बाद फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, मास्टर करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा, बीडीएस और एप्लाइड साइंस में से किसी एक विषय के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक पास करना होगा। अगर आप फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बनना चाहते है, तो आपको एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करनी होगी और इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एमडी भी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, दिल्ली
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हैदराबाद
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़
- डॉ भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी
- बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी

इन संस्थानों से आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि कोर्स कर सकते है।

नीट यूजी के लिए ऐसे करें अप्लाई

भारत में मेडिकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उम्मीदवारों को नीट के लिए परीक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जो कई कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग होती हैं। नीट में शामिल होने के लिए, उम्मीदवारों को एनटीए के तरफ से तय की गई नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करनी होगी। चूंकि, इस बार एनटीए ने नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दी है, इसमें बिना जीव विज्ञान विषय पढ़े छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा क्षेत्र के में विस्तार करने का अहम फैसला लिया है। अब, अलग से विषय के तौर पर जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले उम्मीदवार भी नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह ऐसे छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं।

नीट यूजी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

- सबसे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ऑफिसियल वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर जाए।
- अब, वेबसाइट पर "New Registration" के लिंक को सर्च करके क्लिक करें। अपनी पर्सनल जानकारी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। कोशिश करें कि स्ट्रांग पासवर्ड बनाए और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर लें।
- फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
- इसके बाद "Fill Application Form" के सेक्शन में जाएं और सभी जानकारी सावधानी से भरें। आपको अपनी निजी जानकारी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और सटीक है।
- डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10 वीं और 12 वीं की मार्कशीट आदि। अपलोड किए गए डॉक्युमेंट के साइज और फॉर्मेट वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक होनी चाहिए।
- एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पूरी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें। फॉर्म में सारी जानकारी सही होने पर "Final Submit" बटन पर क्लिक करें।

जरूरी बातें

- अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और किसी भी गलती से बचें, वरना अप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
- एप्लीकेशन फीस का पेमेंट समय से पहले ही कर लें।
- सभी जरूरत के डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- एप्लीकेशन जमा करने से पहले उसकी प्रूफरीडिंग कर लें।
- अधिक जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।

इन टिप्स को करें फॉलो

- परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT की किताबों को पढ़ें।
- पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें।
- पेपर से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शुक्रवार 16 जनवरी 2026

कटाक्षों से घबराती सरकार

सत्ता जब अनैतिक तरीके से पायी और चलायी जाये तो उससे उपजा अपराध भाव सियासतदानों को एक हास्य कलाकार से भी डरा देता है। फिर उसकी आवाज़ दबाने के लिये कानून की बजाय राज्य अपनी मशीनरी तथा संगठन की ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है रविवार को मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में, जहां प्रसिद्ध हास्य कलाकार कुणाल कामरा का शो हुआ था जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीति पर करारे व्यंग्य कसे थे और किसी का भी नाम लिए बिना नेताओं की अवसरवादिता पर कटाक्ष किया था। इससे नाराज़ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमु यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल में जमकर तोड़-फोड़ की, साथ ही कामरा के खिलाफ मामला दर्ज़ कर दिया गया है और उन्हें देश भर में कहीं भी न घूमने-फिरने की चेतावनी दी जा रही है। कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वैसे कुणाल के जिस मज़ाक पर शिंदे गुट के शिवसैनिक नाराज़ हैं व एफआईआर दर्ज़ है उसमें न तो उप मु यमंत्री का नाम लिया गया है और न ही पार्टी के किसी नेता का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि करीब तीन वर्ष पहले शिवसेना और एनसीपी, इन दोनों दलों में जो फूट पड़ी थी, उस पर कुणाल कामरा ने यह कहकर तंज कसा था कि शिवसेना से शिवसेना निकल गयी और एनसीपी से एनसीपी निकल गयी। साथ ही उन्होंने शिंदे को संकेतों में गद्दार कहा। राज्य की भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) व एनसीपी (अजित पवार गुट) की सरकार तथा पार्टी कार्यकर्ताओँ को कुणाल की कॉमेडी ऐसी नागवार गुजरी कि उन्होंने आयोजन स्थल में जमकर तोड़फोड़ की। जिस के बाद 11 उपद्रवी गिर तार हुए हैं। उधर पुलिस ने शिवसेना विधायक व पार्टी प्रवक्ता मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर कुणाल कामरा के खिलाफ को एफआईआर दर्ज की। इतना ही नहीं, मु बई महानगरपालिका का एक दस्ता क्लब को जमींदोज़ करने हेतु भेजा गया। मु यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कामरा की कॉमेडी को %अपमानजनक% बतलाते हुए कहा कि %यह सहन नहीं किया जायेगा।% जबकि शिवसेना विधायक और मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि तोड़फोड़ जैसे काम का वह सरकार में होने के नाते समर्थन नहीं करते, लेकिन मंत्री होने से पहले वे शिवसैनिक हैं और जो हमारे नेता का मज़ाक उड़ाएगा उसे शिवसैनिक छोड़ेंगे नहीं। इस घटना पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का खून उबाल मार रहा है और नेता उसे जायज ठहरा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं हिन्दुस्तान भर में कहीं भी घूमने-फिरने नहीं दिया जायेगा। ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश हस्के का कहना है कि %कामरा एक अनुबंधित कॉमेडियन हैं। मगर उन्हें सांप की पूंछ पर पैर नहीं रखना चाहिए था। एक बार जब नुकीले दांत बाहर आते हैं तो परिणाम भयंकर होते हैं। हस्के ने आरोप लगाया कि कामरा ने उद्धव ठाकरे से पैसे लिए हैं और एकनाथ शिंदे को निशाना बना रहे हैं।% उन्होंने कहा कि %हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे देश में कहीं भी घूम न सकें। हम दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। अगर हम उनका अनुसरण करने लगे तो कामरा को देश छोड़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि कुणाल कामरा समकालीन परिघटनाओं और राजनीति को अपने व्यंग्य के विषय बनाते हैं। एक मायने में उन्हें साहसी व चैतन्य कलाकार माना जाता है जो देश-विदेश की घटनाओं पर अपने तरीके से अपनी राय जाहिर करते हैं। स्टैंडअप कॉमेडी के अलावा वे सोशल मीडिया के जरिये भी सक्रिय रहते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें इस नाते कई लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रसिद्ध हस्तियों से वे उलझ भी चुके हैं। 2020 में इंडिगो की एक लाइट में उनकी मुलाकात सत्ता समर्थक माने जाने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी से जब हुई तो उन्होंने गोस्वामी की पत्रकारिता पर तीखे सवाल किये। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया।

साल 2025-भारत के दामन में कांटे ही कांटे

अनिल जैन

भारत सरकार भले ही दावा करे कि आर्थिक तरक्की के मामले में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वैश्विक आर्थिक मामलों के तमाम अध्ययन संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था का शोकगीत गा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की साख सिर्फ आर्थिक मामलों में ही नहीं गिर रही है, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकार और मीडिया की आजादी में भी भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग इस साल पहले से बहुत नीचे आ गई है। हर कैलेंडर वर्ष अपने दामन में तमाम तरह की कड़वी-मीठी यादें समेटे हुए बिदा होता है। ये यादें अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को लेकर भी होती हैं और राष्ट्रीय घटनाओं से स बन्धित भी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और खेल आदि क्षेत्रों से जुड़ी कड़वी-खट्टी-मीठी यादों की वजह से उस साल को याद किया जाता है। कोई-कोई साल भीषण प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के लिए भी इतिहास के पन्नों में यादगार साल के तौर पर दर्ज हो जाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2025 चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक टकरावों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को पड़ोसी देशों से मिलती चुनौतियों, अभूतपूर्व बेरोजगारी व महंगाई के चलते आम लोगों के लिए दुश्वारियों से भरा रहा। न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख पर पहले से उठ रहे सवाल और ज्यादा गहरे हुए। सरकार की ओर से संसद और संविधान की अवहेलना का सिलसिला भी जारी रहा। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर सत्ता प्रतिष्ठान के हमले बदस्तूर होते रहे। हमेशा की तरह प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही भ्रष्टाचार जनित मानव निर्मित आपदाओं का सिलसिला भी इस साल भी जारी रहा। देश भर में, खास कर उत्तर भारत में यौन अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता रहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश पर एक हिंदुत्ववादी वकील द्वारा जूता उछालने और संसद में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पर देश को गृहयुद्ध में झोंकने का आरोप लगाना भी इस साल की उल्लेखनीय घटना रही।

वर्ष 2025 की शुरुआत प्रयागराज इलाहाबाद में हुए कुंभ से हुई थी। एक महीने तक चले इस विश्वस्तरीय धार्मिक आयोजन के दौरान सरकारी सूचना के मुताबिक 36 लोग मारे गए, जबकि गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अनगिनत लोग घायल हुए। कुंभ के सिलसिले में ही फरवरी महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इन दो दुर्घटनाओं से ऐसे आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन में सरकारी तंत्र की कमजोरी और लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई। इसके बाद जून के महीने में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान गिरने की दर्दनाक घटना, उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा और बेंगलुरू में आईपीएल की जीत के जश्न में मची जानलेवा भगदड़ भी देश को गहरे ज म दे गई। अहमदाबाद की विमान दुर्घटना में 241, उत्तराखंड त्रासदी में 100 से ज्यादा और बेंगलुरू की भगदड़ में 17 लोग मारे गए। साल के आखिरी महीने में देश की एकमात्र एयरलाइंस सेवा इंडिगो में कुप्रबंधन के चलते तीन दिन तक विमान सेवाएं ठप रहीं, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर अभूतपूर्व अफ़रा-तफ़री मची और लाखों लोग बुरी तरह परेशान हुए। यह पूरा संकट सरकार के निजीकरण और एकाधिकार वाले मॉडल का नतीजा रहा।

इन सभी घटनाओं के दरमियान ही 25 अप्रैल को ज मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले 27 पर्यटक मारे गए। इस हमले ने कश्मीर घाटी में कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आतंकवाद खत्म होने के केंद्र सरकार के दावे की भी कलई खोल दी। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। चार दिन तक दोनों देशों के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद संघर्ष विराम हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेशक भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया लेकिन भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के कूटनीतिक प्रयास पाकिस्तान के खिलाफ विश्व राजनीति को प्रभावित करने में नाकाम रहे। इसके विपरीत पाकिस्तान पहली बार वैश्विक शक्तियों का समर्थन हासिल करने में कामयाब होता दिखा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए संघर्ष विराम ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर भी प्रतिकूल असर डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र प ने कई बाद दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम उन्होंने कराया, लेकिन भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक बार भी उनके दावे का खंडन नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आक्रामक आत्मप्रदर्शन के आगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी को दुनिया ने उसकी बेबसी के रूप में देखा। अमेरिका से रिश्तों में खिंचाव के चलते भारत ने चीन और रूस के साथ अपने सर्द पड़े रिश्तों में गरमाहट लाने के प्रयास किए।

वैश्विक राजनीति में कमजोर प्रदर्शन के साथ ही साल 2025 में अर्थव्यवस्था के चरमराने का सिलसिला भी जारी रहा, जिसके नतीजे के तौर पर देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी किस स्तर तक पहुंच गई है, यह जानने के लिए ज्यादा पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थिति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। खुद सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ राशनकार्ड धारकों को हर महीने मु त राशन दिया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर लोगों को दिखाई जा रही है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हुए आंकड़ों की बाजीगरी के जरिये जीडीपी की विकास दर को 8.2 फीसदी बताया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया के देशों में 136वें नंबर पर है और ढोल पीटा जा रहा है कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बन जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने का सिलसिला इस साल भी बना रहा और वह सबसे बुरी तरह पिटने वाली एशियाई मुद्रा बन गया। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहा करते थे कि %जिस देश की करेंसी गिरती है, उस देश की आबरू भी गिर जाती है%, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता रुपये की कीमत गिरने के फायदे बता रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक के रिजर्व कोष दो-दो बार पैसे लिए थे और इस साल उसने जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती की और सरकारी उपक्रमों व सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का सिलसिला जारी रखा। यही नहीं, पैसे के अभाव में ही उसे मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजना को भी बंद करना पड़ा, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा सहारा बनी हुई थी। भारत सरकार भले ही दावा करे कि आर्थिक तरक्की के मामले में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वैश्विक आर्थिक मामलों के तमाम अध्ययन संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था का शोकगीत गा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की साख सिर्फ आर्थिक मामलों में ही नहीं गिर रही है, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकार और मीडिया की आजादी में भी भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग इस साल पहले से बहुत नीचे आ गई है। हालांकि भारत सरकार ऐसी रिपोर्टों को तुरंत खारिज कर देती है; और सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुका मीडिया का एक बडा हिस्सा भी इस मामले में सरकार के सुर में सुर मिलाता है, जबकि यह रेटिंग हमारे यहां होने वाले चुनावी सर्वेक्षण या एग्जिट पोल की तर्ज पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित होती है।

बहुत मुमकिन है कि इस पूरे सूरत-ए-हाल से बेखबर हिंदुत्ववादी विचारधारा के संगठन और विकास का झांसा देकर सत्ता में आए उनके लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने मंसूबे को पूरा करने की दिशा में इस साल को भी अपने लिए उपलब्धियों से भरा मान लें, क्योंकि इस साल उसने राजनीतिक स्तर पर दो बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर 27 साल बाद अपनी सरकार बनाई है और बिहार में उसने पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सत्ता में अपनी साझेदारी बरकरार रखी है। हालांकि दोनों ही जगह उसकी कामयाबी में चुनाव आयोग की विवादास्पद भूमिका मददगार रही।

वैसे सावरकर-गोलवलकर प्रणित हिंदुत्व की विभाजनकारी विचारधारा को बढ़त तो 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही मिलने लगी थी लेकिन उसके दूरगामी नतीजे 2019 से आना शुरू हुए थे जो साल 2024 में और अब 2025 में तो बहुत साफ तौर पर नजर आए हैं। कुल मिलाकर इस समय देश का जो परिदृश्य बना हुआ है, वह आने वाले सालों में हालात और ज्यादा संगीन होने के संकेत दे रहा है।

मनरेगा को मारकर आया जी राम जी

योगेन्द्र यादव

सरकार ने इस योजना का हर महत्वपूर्ण प्रावधान पलट दिया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में और उस राज्य के किस इलाके में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार हर राज्य के लिए बजट की सीमा तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि खेती में मजदूरी के मौसम में किन दो महीनों में इस योजना को स्थगित किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर क्या काम होगा, उसका फैसला भी ऊपर से निर्देशों के अनुसार होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसका खर्चा उठाने की ज़ि मेवारी राज्य सरकारों पर भी डाल दी गई है।

विपक्ष को ऐतराज़ है कि जिस ऐतिहासिक योजना को देश %महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना% उर्फ %मनरेगा% के नाम से जानता रहा है, उसके नाम से महात्मा गांधी को क्यों हटाया जा रहा है। यूँ भी सरकार द्वारा पारित नया नाम- %विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक% उर्फ %%वीबी-जी राम जी विधेयक%—काफ़ी अटपटा था। पहले अंग्रेज़ी के %एक्रोनिम% को सोचकर हिंदी के शब्द गढ़ने के इस तरीके में मैकॉले की गंध आती थी, लेकिन %मनरेगा% की जगह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून का मसौदा देखकर लगा कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम मिटाकर ठीक ही किया। जब इस योजना की आत्मा ही नहीं बची, जब इसके मूल प्रावधान ही खत्म किए जा रहे हैं, तो नाम बचाने का क्या फ़ायदा।

पहले समझ लें कि मनरेगा नामक यह क़ानून क्यों ऐतिहासिक था। आज़ादी के कोई साठ साल बाद भारत सरकार ने इस क़ानून के ज़रिए पहली बार अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने की दिशा में एक कदम उठाया था। संविधान के %नीति निर्देशक सिद्धांत% के तहत %अनुच्छेद 39(ड्ड) और 41% सरकार को हर व्यक्ति के लिए %आजीविका के साधन% और %रोजगार का अधिकार% सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। छह दशकों तक इसकी अनदेखी करने के बाद वर्ष 2005 में %संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन% (यूपीए) सरकार ने संसद में %राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम% पास किया और पहली बार देश के अंतिम व्यक्ति को इस बाबत एक हक दिया। यह कानून स पूर्ण अर्थ में रोजगार की गारंटी नहीं था, लेकिन इसके प्रावधान किसी सामान्य सरकारी रोजगार योजना से अलग थे।

यह क़ानून ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह सरकार से रोजगार की मांग कर सके। इसमें सरकारी अफ़सरों के पास किंतु-परंतु या बहानेबाजी की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी गई थी। इस योजना का लाभ लेने की कोई पात्रता नहीं है। कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अपने %जॉब कार्ड% बनवाकर इसका लाभ उठा सकता है।

रोजगार मांगने के लिए कोई शर्त नहीं है - जब भी रोजगार मांगा जाए, उसके दो सप्ताह में सरकार या तो उस व्यक्ति को काम देगी या फिर मुआवजा। इस योजना का अनूठा प्रावधान यह है कि इसमें बजट की कोई सीमा नहीं है- जब भी, जितने लोग चाहें, काम मांग सकते हैं और केंद्र सरकार को पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस तरह अधूरा ही सही, लेकिन पहली बार रोज़गार के अधिकार को क़ानूनी जामा पहनाने की कोशिश हुई। दुनिया भर में इस योजना पर चर्चा हुई थी।

व्यवहार में यह क़ानून अपनी सही भावना के अनुरूप कुछ साल ही लागू हो पाया। %मनरेगा% की दिहाड़ी बहुत कम थी और सरकारी बंदिशें बहुत ज़्यादा। फिर भी मनमोहन सिंह सरकार ने इसका विस्तार किया। %यूपीए% सरकार जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क़ानून की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि वे इसे %यूपीए% के शेखचिल्लीपन के यूजियम के रूप में बचाए रखेंगे। पहले कुछ वर्षों मोदी सरकार ने इस योजना का गाला घोंटने की कोशिश भी की, लेकिन %कोविड% आपदा के समय मोदी सरकार को इसी योजना का सहारा लेना पड़ा। सरकार की कोताही, अफसरशाही की बदनीयत और स्थानीय भ्रष्टाचार के बावजूद %मनरेगा% ग्रामीण भारत के अंतिम व्यक्ति के लिए सहारा साबित हुई।

पिछले 15 वर्षों में इस योजना के चलते 4,000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। हर वर्ष कोई 5 करोड़ परिवार इस योजना का फायदा उठाते रहे। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी। %कोविड% जैसे राष्ट्रीय संकट या अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान %मनरेगा% ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका।

अब मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना को दफन करने का मन बना लिया है। जाहिर है, ऐसी किसी योजना को औपचारिक रूप से समाप्त करने से राजनीतिक घाटा होने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए घोषणा यह हुई है कि योजना को %संशोधित% किया जा रहा है। झांसा देने के लिए यह भी लिख दिया गया कि अब 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी, लेकिन यह गिनती तो तब शुरू होगी जब यह योजना लागू होगी, जब इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। हकीकत यह है कि सरकार द्वारा संसद में पारित %वीबी - जी राम जी विधेयक% एक तरह से रोजगार गारंटी के विचार को ही ख़त्म करता है। अब यह हर हाथ को काम के अधिकार की बजाय चुनिंदा लाभार्थियों को दिहाड़ी के दान की योजना बन जाएगी।

सरकार ने इस योजना का हर महत्वपूर्ण प्रावधान पलट दिया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में और उस राज्य के किस इलाके में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार हर राज्य के लिए बजट की सीमा तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि खेती में मजदूरी के मौसम में किन दो महीनों में इस योजना को स्थगित किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर क्या काम होगा, उसका फैसला भी ऊपर से निर्देशों के अनुसार होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसका खर्चा उठाने की ज़ि मेवारी राज्य सरकारों पर भी डाल दी गई है।

पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, अब सिफ़ 60 प्रतिशत देगी। जिन ग़रीब इलाक़ों में रोज़गार गारंटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां की ग़रीब सरकारों के पास इतना फण्ड होगा ही नहीं और केंद्र सरकार अपने हाथ झाड़ लेगी। यानी ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हां, अगर किसी राज्य में चुनाव जीतने की मजबूरी हुई तो वहां अचानक रोज़गार गारंटी का फण्ड आ जाएगा। जहां विपक्ष की सरकार है वहां इस योजना को या तो लागू नहीं किया जाएगा, या फिर उसकी सख़्त शर्तें लगायी जायेंगी। अच्छा हुआ जो ऐसी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। जिन्हें गांधी का विचार प्यारा है उन्हें संसद में इस विधेयक के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी, उन्हें देश के मानस में %मनरेगा% की हत्या की ख़बर पहुचानी होगी, उन्हें किसानों की तरह सड़क पर संघर्ष करना होगा।

विविध समाचार

लुधियाना पश्चिम उपचुनाव : मतदाता सूची संबंधी 24 अप्रैल तक दायर किए जा सकते हैं दावे और ऐतराज : सिबिन सी

चंडीगढ १५/०१ (संवाददाता): 64–लुधियाना पश्चिम विधानसभा हलके के उप चुनाव से पहले, फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 1 अप्रैल, 2025 है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मसौदे के अनुसार, 64–लुधियाना पश्चिम में मतदाताओं की कुल गिनती 1,73,071 है। दावे और ऐतराज 24 अप्रैल, 2025 तक दायर किए जा सकते हैं। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशना 5 मई, 2025 को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तर्कसंगता और अनुमति के बाद हलके में पोलिंग स्टेशनों की कुल गिनती 192 है, जो कि सभी शहरी क्षेत्र में हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की गिनती 1,200 से अधिक न हो, ताकि पहुंच और सुविधा को बढ़ाया जा सके। मतदाता सूची और चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों संबंधी सिबिन सी ने पहले ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर मीटिंग की है। उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा पहले ही अपने बूट लेवल एजेंटों (बी.एल.एज) की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य पार्टियों को पारदर्शी चुनाव भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस पालन करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिबिन सी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मतदाताओं को अपडेट करने के बारे में जागरूकता पैदा करने और दावे और ऐतराज दर्ज करने की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए बूथ स्तर एजेंटों (बी.एल.एज) के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की है। इसके अलावा, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात पर भी रौशनी डाली कि मतदाता, दावों और ऐतराजों संबंधी आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट (डीईओ) के पास सेक्शन 22 या 23 तहत अपील कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का नाम अनजाने में रह गया हो, तो उसे शामिल करने के लिए भी अपील की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह अपील मुख्य चुनाव अधिकारी तक भी ले जाई जा सकती है, जैसा कि प्रतिनिधित्व कानूनोंधिनियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

हिमाचल में दो पुलिसकर्मी नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के आरोप में बर्खास्त

शिमला १५/०१ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में संलिप्तता के आरोप में दो पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार और जुगल किशोर को बर्खास्त कर दिया है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के अनुसार राज्य के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए। शिमला पुलिस में तैनात दोनों कांस्टेबलों को कथित संलिप्तता सामने आने के बाद शुरू में कैंथू पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों को जवाब देने का अवसर देते हुए औपचारिक नोटिस दिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनके जवाबों की समीक्षा की और उन्हें असंतोषजनक पाया, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया। जांच में पता चला कि दोनों कांस्टेबलों के शाह सिंडिकेट से संबंध थे, जो इस क्षेत्र में सक्रिय एक कुख्यात नशीले पदार्थ को तस्करी गिरोह है। इस कदम को व्यापक रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की ओर से एक सख्त संदेश और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के प्रति इसकी शून्य–सहिष्णुता नीति का प्रतिबिंब माना जा रहा है। यह आंतरिक जवाबदेही और अनुशासन की ओर प्रशासनिक ध्यान में बदलाव का भी संकेत देता है। पुलिस ने कहा कि व्यापक कार्रवाई में शिमला जिले में 24 सरकारी कर्मचारियों को चिट्टा नामक सिंथेटिक नशीले पदार्थ की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और राजस्व जैसे विभागों के अधिकारी शामिल हैं दृजिनमें डॉक्टर, शिक्षक, तहसील कल्याण अधिकारी, वन रक्षक और पटवारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 60 सरकारी कर्मचारी ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए हैं।

पुलिस ने सभी आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। दो कांस्टेबलों की बर्खास्तगी के बाद, अन्य आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की संभावना है।

जालंधर में तेज रफ्तार कार ने 3 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, बच्चे का मुंडन करवाने जा रहा था परिवार

जालंधार१५/०१ (संवाददाता): जालंधर के किशनपुरा चौक के पास सोमवार सुबह एक सफेद रंग की तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान त्रिपुर (3) के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार, आज बच्चे का मुंडन था और वे धार्मिक स्थल पर जाने के लिए घर से बाहर खड़े थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आई, जो पहले एक कुत्ते को कुचलते हुए गुजरी। परिवार का ध्यान कुत्ते की ओर गया, और तभी उन्होंने देखा कि वही कार चालक उनके बच्चे को भी कुचल चुका था। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के सदस्य सोमनाथ ने बताया कि वह बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी एक सफेद रंग की तेज रफ्तार गाड़ी आई। उन्होंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी चालक ने रुकने के बजाय और तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान बच्चा कार के टायर के नीचे आ गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस को इस हादसे की सूचना दे दी गई है और परिवार ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की अपील की है। मृतक की दादी, अमरजीत कौर ने बताया कि वह घर में मौजूद थीं और आज मुंडन के लिए परिवार इकट्ठा हो रहा था। अचानक जब बाहर से शोर सुनाई दिया, तो वह बाहर जाकर देखी कि गाड़ी चालक ने बच्चे को कुचल दिया था। थाना रामा मंडी के एएसआई बलकरण सिंह ने बताया कि उन्हें किशनपुरा चौक के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

रोपड़ : पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का थाने के बाहर प्रदर्शन

रोपड १५/०१ (संवाददाता): यहां के सिटी थाने में पुलिस हिरासत में रखे गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक 25 वर्षीय प्रिंस बहादुर को पुलिस 16 अप्रैल को किसी मामले के संबंध में थाने लेकर आई थी। आज सुबह करीब 3 बजे प्रिंस की मौत की खबर सामने आई। युवक की हिरासत में हुई मौत के बाद से ही परिजन आक्रोशित हैं और पुलिस की कार्रवाई व मौत के कारणों पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल, सिटी थाने का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस संवेदनशील मामले की न्यायिक जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रिंस बहादुर शादीशुदा थे और उनका एक पांच साल का बेटा भी है।

वरिष्ठ माध्यमिक सेक्शन्स को को–एजुकेशनल बनाया जाएगा : सुक्खू

शिमला १५/०१ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राजकीय पाठशालाओं के वरिष्ठ माध्यमिक सेक्शन्स को को–एजुकेशनल बनाया जाएगा। सुक्खू ने यहां शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों का युक्तिकरण करेगी, जहां विद्यार्थियों का नामांकन कम है और नजदीक ही समान स्तर का अन्य स्कूल कार्यशील है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर और शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मत्स्य पालन की आठ सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

चंडीगढ़ १५/०१ (संवाददाता): हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की आठ सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए, इन सेवाओं की समय–सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आशय की एक अधिसूचना शुक्रवार को जारी की है। इसके अनुसार सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती तालाबों तथा निजी तालाबों के सुधार के लिये सब्सिडी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी।

सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के साथ–साथ मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों के कल्याण के लिये, मछली या मछली उत्पाद की बिक्री के लिये रेहड़ी सहित स्टोव्ह गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद–खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस तीन दिन के अन्दर जारी किया जाएगा। इन सभी सेवाओं के लिए सम्बन्धित जिले के मत्स्य पालन अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित उप–निदेशक, मत्स्य पालन को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

प्रदेश सरकार खेल को केवल करियर ही नहीं, बल्कि जीवन शैली बनाने की दिशा में कर रही है कार्य : सीएम सैनी

चंडीगढ १५/०१ (संवाददाता): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार खेल को केवल एक करियर ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में स्कूल स्तर से ही खेलों को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि बचपन से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपये का मेडिकल बीमा कवर देने का संकल्प लिया गया है।श्री नायब सिंह सैनी रोहतक जिला के गांव किलोई स्थित श्री शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम परिसर में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता का बतौर मुख्यातिथि विधिवत शुभारंभ करने उपरांत उपस्थितगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिव कुमार स्मृति स्टेडियम के कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि, गांव में शीघ्र महिला चौपाल का निर्माण तथा गांव की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने की भी घोषणा की। उन्होंने स्वर्गीय शिव कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि उनकी स्मृति हमें देश के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देती रहेगी। यह उनकी सोच का प्रतीक है, जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाना चाहती थी। मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये गए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, 224 खिलाडियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास–वन से क्लास–थ्री तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक जीतने वाले खिलाडियों को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देता है। प्रदेश में अब तक खिलाडियों को 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाडियों को मानदेय भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29 हजार से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। खेल विभाग द्वारा 15 हजार 634 खिलाडियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। खिलाडियों को बचपन से ही तराशने के लिए 1,489 खेल नर्सरियां संचालित की जा रही है, जिनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाडियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाडियों को 2000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है, जो केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि इसमें टीम वर्क, अनुशासन, रणनीति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी परीक्षण होता है। यह युवाओं में एकजुटता, समर्पण और अनुशासन का विकास करता है। ऐसे खेलों से ही हम एक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूक समाज की नींव रखते हैं। ऐसे अखिल भारतीय टूर्नामेंट का आयोजन हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। यह न केवल राज्य के खेल जगत में एक नया मुकाम स्थापित कर रहा है, बल्कि इससे किलोई जैसे गांवों को भी राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह टूर्नामेंट केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह स्वर्गीय शिव कुमार के समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना की जीवंत स्मृति है। उन्होंने अपने जीवनकाल में खेलों और समाज सेवा को महत्व दिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनके इन विचारों को जीवित रखा गया है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हरियाणा की धरती शुरू से ही वीरों, खिलाडियों और मेहनतकश किसानों की भूमि रही है। यहां के गांव–गांव से खेल प्रतिभाएं निकलती रही हैं, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वह कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो या फिर बास्केटबॉल, हरियाणा के बेटों और बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को भी प्रोत्साहन देती हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, शुक्रवार 16 जनवरी 2026

मकर संक्रांति का उत्सव भक्ति, रीति-रिवाज और जोश के साथ मनाया गया

भुवनेश्वर १३/०१ (संवाददाता): बुधवार को ओडिशा सहित पूरे देश में मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है, जो हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह त्योहार देश भर में एक जीवंत माहौल लाता है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में इस अवसर को अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है।

सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा शुभ दिन का प्रतीक है मकर संक्रांति सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो उत्तरायण की शुरुआत का संकेत देता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र स्नान करने और दान करने से आध्यात्मिक पुण्य और समृद्धि मिलती है। नतीजतन, मंदिरों और पवित्र स्थलों पर धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान व्यापक रूप से किए जा रहे हैं। मंदिर और शहर उत्सवों से गुलजार ओडिशा के प्रमुख मंदिरों में काफी चहल-पहल देखी गई, पुरी श्रीमंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए। अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में, श्रीमंदिर से मां लक्ष्मी द्वारा लाए गए मकर चावल को पीठासीन देवता को चढ़ाया जाना है।

भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए, प्रशासन ने उत्सवों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मयूरभंज जिले में, मकर संक्रांति को एक सामूहिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें निवासी नए कपड़े पहनते हैं और घर पर पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इस बीच, दक्षिणी ओडिशा में भोगी, एक संबंधित त्योहार मनाया जा रहा है। बेरहामपुर शहर भी उत्सव की खुशी में डूबा हुआ है, खासकर तेलुगु समुदाय के बीच, जहां उत्सव तीन दिनों तक चलता है, जो खुशी, सांस्कृतिक एकता और भक्ति को दर्शाता है।

मकर संक्रांति पर पुरी में भगवान जगन्नाथ को दुनिया का सबसे बड़ा पान चढ़ाया गया

पुरी १३/०१ (संवाददाता): मकर संक्रांति के अवसर पर आज ओडिशा के पुरी श्रीमंदिर में भगवान जगन्नाथ को दुनिया का सबसे बड़ा पान अर्पित किया गया .इस विशाल पान की ऊंचाई डेढ़ फीट से लेकर ढाई फीट तक होती है। श्रीमंदिर के हडपा नायक सेवकों द्वारा मंदिर परिसर के भीतर ही अत्यंत सावधानी और श्रद्धा से इस विशाल पान को तैयार किया जाता है।इस विशाल पान को तैयार करने के लिए लगभग सात कड़े (बंडल) पान के पत्तों का उपयोग किया जाता है। लौंग की सहायता से पत्तों को सावधानीपूर्वक एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे यह विशाल संरचना बनती है।सुपारी, इलायची, कपूर, चंदन, केसर और अन्य सुगंधित पदार्थों जैसी सुगंधित और पवित्र सामग्री को इसकी पवित्रता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है।यह विशेष पान द्विप्रहारा धूप (दोपहर के भोजन की आहुति) के अनुष्ठान के दौरान देवता को अर्पित किया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार, धनु संक्रांति पर देवी महालक्ष्मी अपने मायके के लिए प्रस्थान करती हैं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, वे फूलों की मालाओं से सजी हुई श्री मंदिर लौटती हैं। मकर चूल्हा, ताड़ा बेसा, विशाल पान ढोते हुए। ऐसा माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने और उन्हें शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की भेंट लाती हैं, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वे नाराज या अप्रसन्न न हों। मकर संक्रांति का एक और प्रमुख आकर्षण 84 प्रकार के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का अर्पण है, जो इस शुभ दिन महाप्रभु को अर्पित किए जाते हैं।

सेवायत विवाद के कारण लिंगराज मंदिर में अनुष्ठान बाधित

भुवनेश्वर १३/०१ (संवाददाता): ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में सेवादारों के बीच विवाद के कारण बुधवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी भगवान लिंगराज की पूजा-अर्चना एक बार फिर रुक गई है। बडू और सुआर निजोगों के बीच पिछले विवाद और बढ़ गए हैं, जिससे कल से मंदिर की पूजा-अर्चना बाधित हो गई है। इस गतिरोध के कारण बाबा लिंगराज के सामने सभी चढ़ावे रुक गए हैं, जिससे भक्तों में व्यापक गुस्सा है। सूत्रों के अनुसार, यह विवाद खीर औटा अनुष्ठान को लेकर शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात पर तीखी बहस हुई कि कौन यह अनुष्ठान करेगा। इस विवाद के कारण, कल संध्या धूप के बाद से कोई भी अनुष्ठान नहीं किया गया है।

अतीत में बार-बार व्यवधान की खबरें अतीत में भी बडू और सुआर निजोगों के बीच इसी तरह के व्यवधान की खबरें आई हैं, जिससे भगवान लिंगराज की पूजा-अर्चना रुक गई थी। पिछले साल, भगवान लिंगराज के नबंका बेढ़ा अनुष्ठान के दौरान, समूहों के बीच खीर औटा के प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया था। झड़पों को देखते हुए, मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया और मुद्दे को हल करने के लिए एक निर्देश जारी किया।

जारी आदेश के अनुसार, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, परबा यात्रा बिसोई को खीर औटा के लिए जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था करने और एक अस्थायी चूल्हा तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जबकि घंटा और मेघा डंबरा सेवादारों को घृत कमला अनुष्ठान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बडू निजोग के सचिव कमलाकांत बडू ने जिला कलेक्टर के निर्देश को अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने आदेश दिया कि देवता के नबंका बेढ़ा अनुष्ठान को अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रखा जाए। परिणामस्वरूप, नबंका बेढ़ा अनुष्ठान कल शाम से निलंबित है, लिंगराज मंदिर के पर्यवेक्षक राजकिशोर महापात्र ने बताया। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी बाबा लिंगराज की पूजा-अर्चना न होने से भक्तों में तीव्र असंतोष देखा गया है।

ठेकेदार के गोदाम में आग लगाई गई, माओवादी एंगल से इनकार किया गया

कालाहांडी १५/०१ (संवाददाता): ओडिशा के कालाहांडी जिले में नरला पुलिस स्टेशन के तहत रूपरा रोड पर चटामहुल में बदमाशों ने एक ठेकेदार के गोदाम में आग लगा दी, जिससे सोमवार देर रात इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती जांच में गोदाम के अंदर कई जगहों पर माओवादियों के नाम और निशान वाले पोस्टर चिपके मिले। बताया जा रहा है कि पोस्टरों में अगले एक साल के अंदर और गोदामों में आग लगाने और गोदाम मालिक के परिवार को धमकी देने की बात लिखी थी। सूत्रों ने बताया कि परिसर से चार अलग-अलग पोस्टर बरामद किए गए। एक पोस्टर में कथित तौर पर लिखा था कि 48 घंटे के अंदर कार्तिक नाम के एक गोदाम कर्मचारी को मार दिया जाएगा। पोस्टरों में यह भी कहा गया था कि ठेकेदार के दूसरे गोदामों में भी साल भर के अंदर आग लगा दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोदाम मालिक की गाड़ी के अंदर एक माओवादी पोस्टर मिला था, जिसमें 37 लाख रुपये की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान यह पता चला कि गोदाम मालिक का बेटा कथित तौर पर धमकियां देने में शामिल था। उसे इस मामले में जेल भेज दिया गया था और करीब एक महीने पहले उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

नुकसान और आधिकारिक स्पष्टीकरण स्थानीय लोगों ने सोमवार देर रात आग देखी और परिवार और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दो टीमें भेजी गईं। गोदाम में ट्यूबवेल खोदने से संबंधित सामान जैसे पाइप, टैंक और पुरानी गाड़ियां रखी थीं, जिन्हें काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के समय गोदाम मालिक दिनेश अग्रवाल एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल कारणों से गांव से बाहर थे। खबर लिखे जाने तक किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। कालाहांडी के पुलिस अधीक्षक नागराज देवराकोंडा ने साफ किया कि इस घटना का माओवादियों से कोई लेना-देना नहीं है और पोस्टरों को फर्जी बताया।

शराब के नशे में मां-बाप ने 6 महीने के बच्चे की ले ली जान

कटक १५/०१ (संवाददाता):ओडिशा के कटक में चौद्वार थाना व्याघ्रवाहिनी मैदान के पास मौजूद आदिवासी बस्ती में एक दुखद घटना घटी है। शराब के नशे में धुत होकर मां.बाप ने अपने 6 महीने के बेटे को मार डाला। इसके बादए उसे सुनसान जगह पर दफ्ना दिया। थाने में मिली शिकायत के बाद चौद्वार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने लाश को बरामद किया। अब पुलिस ने घटना की छानबीन में शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसारए सोमवार को आदिवासी बस्ती के राजू हेंब्रम और संभारी हेंब्रम अपने तीन दोस्तों के साथ घर के अंदर बैठकर देर रात तक शराब पी रहे थे। अधिक नशा होने के बाद दोनों वहां सोये हुए 6 महीने के बच्चे के ऊपर चढ़ गए।इसके बारे में दोनों को उस वक्त पता नहीं चलाए लेकिन मंगलवार की सुबह जब नशा उतरा तो दोनों ने अपने बेटे को मृत पाया। ऐसे में पति.पत्नी ने हड़बड़ी में आकर बच्चे की लाश को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मिट्टी खोदकर उसे दफ्ना कर दिया। इस संबंध में पड़ोस के लोग और कुछ युवाओं को जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत चौद्वार थाना को इस बारे में खबर दी। थाना अधिकारी विश्व रंजन साहू ने मौके पर पहुंचने के बाद साइंटिफिक टीम को बुलाया। साइंटिफिक टीम भी मौके पर पहुंच कर घटना की अधिक छानबीन में जुट गई है। बाद में मजिस्ट्रेट पहुंचने के बाद मिट्टी के नीचे से दफ्नाए गए 6 महीने के बच्चे के लाश को निकाला गया और उसे पंचनामा करने के लिए कटक बड़ा मेडिकल को भेजा गया। पुलिस बच्चे की मां.बाप से अधिक पूछताछ में जुटी है। इसको लेकर एक मामला भी दर्ज की गई है। उधर जगतसिंहपुर जिले के तिर्तोल थाना क्षेत्र के शिरस्ता गांव में दो लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत फूड प्वाइजनिंग या ड्रिंक की वजह से हुई है।

शटर काटकर 50 लाख के सोने-चांदी के गहने लूटे गए

केंद्रपाड़ा १५/०१ (संवाददाता): देर रात एक हिम्मत वाली चोरी में, बदमाशों ने शटर काटकर एक ज्वेलरी की दुकान से करीब 50 लाख रुपये के गहने लूट लिए। बताया जा रहा है कि यह घटना केंद्रपाड़ा सदर पुलिस स्टेशन इलाके के ठाकुरहाट के पास एक ज्वेलरी की दुकान में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाशों ने कथित तौर पर लगभग 220 ग्राम सोना और 12 किलो चांदी के गहने लूटे।

लूटपाट के बाद, आरोपी दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान क्राइम सीन से एक गैस कटर, एक हेलमेट और दस्ताने बरामद किए। सभी सबूत जब्त कर लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्वेलरी की दुकान के मालिक दीप्ति रंजन साहू ने बताया कि देर रात अपने मोबाइल फोन पर फुटेज देखते समय उन्होंने दुकान के अंदर दो-तीन लोगों को खड़े देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को आते देख बदमाश मौके से फरार हो गए।

घटना के बारे में बताते हुए दुकान के मालिक ने कहा, मैं रात 1 से 2 बजे के बीच अपने मोबाइल फोन पर अपनी दुकान का फुटेज देख रहा था। लाइव फीड के दौरान, मैंने दुकान के बाहर दो-तीन अनजान लोगों को खड़े देखा। कुछ ही देर बाद, मैंने उन्हें दुकान में घुसते और एक बैग में गहने इकट्ठा करते देखा। वे लॉकर नहीं तोड़ पाए, लेकिन उसके बाहर रखे सभी गहने लूटने में कामयाब रहे। चांदी के सभी गहने और 1 ग्राम सोने के गहने चोरी हो गए हैं। केंद्रपाड़ा सदर पुलिस ने इस घटना की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ओडिशा नाविक संघ ने दो समाजसेवियों को समानित किया

भुवनेश्वर १५/०१ (संवाददाता): सीफेयरर्स एसोसिएशन ऑफ ओडिशा (स्ह) ने दुनिया भर में मुश्किल में फंसे नाविकों की बिना किसी स्वार्थ के और लगातार मदद करने वाले दो लोगों को सम्मानित किया है। कैप्टन वाई मनोज जॉय तीन दशकों से ज्यादा समय से नाविकों और उनके परिवारों के लिए बिना थके मदद करने वाले एक स्तंभ रहे हैं। वह मुश्किल में फंसे नाविकों को इमोशनल सपोर्ट और सुसाइड रोकने में मदद देने वाली 24*7 हेल्पलाइन चलाने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह, एक अनुभवी ऑयलमैन, पीआर बारिक ने लगातार अपनी शोर लीव और कॉन्ट्रैक्ट के बीच की छुट्टियों को ज़रूरतमंद नाविकों की मदद के लिए समर्पित किया है, एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा। इस सम्मान समारोह में मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन अशोक महापात्रा भी शामिल हुए।

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कैप्टन नवीन चंद्र सरमा ने कहा, समाज में समुद्री समुदाय का योगदान ज़्यादातर चुप रहता है और अक्सर दिखाई नहीं देता। मर्चेंट नेवी के बिना, दुनिया की लगभग आधी आबादी भूख से जूझेगी, और बाकी आधी आबादी के पास एनर्जी और रिसोर्स नहीं होंगे।

राउरकेला हाफ मैराथन-2026 को मिल रही जबरदस्त उत्साही प्रतिक्रिया, 5500 से अधिक धावकों के पंजीकरण के कारण पंजीकरण बंद

राउरकेला १५/०१ (संवाददाता): राउरकेला हाफ मैराथन-2026 के उद्घाटन संस्करण को देशभर के दौड़ प्रेमियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। पंजीकरण की अंतिम तिथि से काफी पहले ही 5,500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करा लिया, जिसके चलते पंजीकरण प्रक्रिया बंद करनी पड़ी। उत्साहपूर्ण भागीदारी इस आयोजन के पहले संस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस्पात नगरी में बढ़ती तंदरुस्ती / फिटनेस और खेल संस्कृति को दर्शाती है। कुल पंजीकरणों में से 900 से अधिक धावकों ने प्रमुख 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन श्रेणी के लिए पंजीकरण किया है, जो इस पैमाने के पहले आयोजन के लिए एक उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा, राउरकेला के आसपास के गांवों से 2000 से अधिक धावकों ने भी मैराथन के लिए पंजीकरण कराया है। सभी श्रेणियों में भारी संख्या में प्रतिभागियों की उपस्थिति पेशेवर एथलीटों, शौकिया धावकों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के बीच मैराथन की व्यापक लोकप्रियता को रेखांकित करती है। उत्साह को और बढ़ाते हुए, राउरकेला हाफ मैराथन-2026 में डॉ. सुनीता , रचित्रा मिस्त्री, अनुराधा बिस्वाल, मिनाती महापात्र, सुनील पात्र, बीरेंद्र लकड़ा और कई अन्य प्रख्यात खेल सितारों सहित कई प्रसिद्ध खेल हस्तियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी, जिनसे प्रतिभागियों को प्रेरणा मिलेगी और आयोजन की गरिमा और ऊँचाइयों तक पहुँचेगी। गौरतलब है कि, मैराथन में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 4 श्रेणियाँ होंगी, जिनमें 21.1 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 2 किमी (भिन्नाक्षम व्यक्तियों के लिए) शामिल हैं। सभी श्रेणियों के विजेताओं के लिए कुल 7,70,800 रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। 21.1 किलोमीटर वर्ग में दोनों आयु वर्ग के पुरुष और महिला प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमश 31,000 रुपये और 21,000 रुपये दिए जाएँगे। इसी वर्ग के अगले 5 विजेताओं को 1000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार, 10 किलोमीटर वर्ग में दोनों आयु वर्गों के पुरुष और महिला वर्ग के प्रथम पुरस्कार विजेता को 21,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, इसके बाद द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमश 11,000 रुपये और 7,100 रुपये दिए जाएँगे। अगले 5 विजेताओं को 750 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ में, दोनों आयु वर्गों के पुरुष और महिला वर्ग के प्रथम विजेताओं को 5100 रुपये, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश 3100 रुपये और 2100 रुपये दिए जाएंगे। 2 किलोमीटर दौड़ की खुली श्रेणी में, पहले तीन विजेताओं को क्रमश 5100 रुपये, 3100 रुपये और 2100 रुपये दिए जाएँगे, और अगले 5 विजेताओं को 500 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 10 ग्रामीण प्रतिभागियों को 5,000 रुपये प्रत्येक का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि अगले 20 ग्रामीण प्रतिभागियों को 1000 रुपये का प्रतीक उपहार प्रदान किया जाएगा। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, शीर्ष 10 ग्रामीण स्कूली छात्रों में से प्रत्येक को 1,500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मैराथन को निर्धारित समय में पूरा करने वाले प्रत्येक धावक को पदक और एक डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

राउरकेला हाफ मैराथन-2026 का उद्देश्य तंदरुस्ती, धैर्य एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है, साथ ही राउरकेला को प्रमुख खेल आयोजनों के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण और जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ यह आयोजन इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वार्षिक खेल आयोजन बनने की दिशा में अग्रसर है।